RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

उत्तर प्रदेश म आथिक विकास तथा रोजगार – सृजन

विनोद कुमार
Email: ashisharya95@gmail.com
Mob- No. 07785021796

देश की आर्थिक–संवृद्धि की 7.5 : दर से जुड़ी विडम्बना यह है कि इससे रोजगार के अपेक्षित अवसर सृजित नहीं हो पाये है। आर्थिक सुधारों के दौरान आर्थिक विकास का अनुभव बताता है कि उच्च विकास दर पर्याप्त रोजगार सृजित करने में असफल रही है। वास्तविक धरातल पर अर्थशास्त्रियों तथा नीति–निर्माताओं का यह मॉडल कम से कम भारत में तो असफल हो ही गया है कि आर्थिक विकास की ऊँची दर रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर बेराजगारी दूर करने में सहायक होता है। एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 80 के दशक में 0.28 तथा 90 के दशक में 0. 31 रोजगार लोच–शीतल के साथ रोजगार सृजन सबसे कम रहा है।

सेबी के पूर्व आर्थिक परामर्शदाता एम0वाई0 खान का कहना है कि आर्थिक विकास की ऊँची दर तथा ऊँची वैश्विक रैकिंग के बावजूद भारत में ग्रामीण और अर्द्ध–नगरीय क्षेत्रों मे निर्धनों का एक बड़ा वर्ग उच्च प्रौद्योगिकी उपयोग जनित आर्थिक विकास का लाभ लेने से वंचित रहा है, जबकि उत्पादन में बढ़ती पूंजी, सघनता तथा औद्योगिक क्षेत्रक की पूर्नसंरचना के कारण उच्चतर आर्थिक विकास से भी रोजगार सृजित नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 60 वें चक्र के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2010.11 में देश को रोजगार प्राप्त करने लायक कुल जनसंख्या में से मात्र 42: जनसंख्या ही काम में लगी हुई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में 56 : तथा शहरी भारत में 63 : लोग बेकार हैं। 60 वें चक्र के सर्वे से यह पता चलता है कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में पुरूषों में बेरोजगारी दर 9: थी जो 2003–04 की अपेक्षा 5.6 : अधिक है और शहरी क्षेत्रों में यह 8.1: थी जो 2003–04 के शहरी क्षेत्रों में 6.7: के आंकडें से अधिक है। इसके तदनुरूप स्त्रियों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में 11.7: था जो 2003–04 के 10.5: से ऊँचा था। जाहिर है कि समग्र बेरोजगारी दर जो 2003–04 में 7.3: थी बढ़कर 2010–11 में 9: से अधिक हो गयी है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की गई पाचवीं आर्थिक गणना के आंकड़े 12 जून 2011 को जारी किए गए इस गणना के आंकड़ो में 1998 से 2011 के बीच गैर–कृषि उद्यमों की संवृद्धि एवं इनमें रोजगार की प्रवृत्तियों के कुछ रोचक तथ्य सामने आये है। आंकड़े दर्शाते हैं कि उद्यमों एवं रोजगार की संवृद्धि में तेजी अपेन के बाद भी आलोच्य अवधि में बेराजगारी दर में वृद्धि हुई है साथ ही निध्रनता के स्तर में कोई उल्लेखनीय कमी नही आयी है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 60 वें चक्र के आँकड़ों से तथा पंचवर्षी आर्थिक गणना के तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि आर्थिक सुधारों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था ने विगत कुछ वर्षों में 6.8 की ऊँची वार्षिक संवृद्धि दर भले ही प्राप्त कर ली हो, लेकिन यह उच्च संवृद्धि दर पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं कर पायी है। इसके कुछ कारण है

1. कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर, सम्पूर्ण जनसंख्या से अधिक रहना तथा श्रम बल की भागीदारी कर विशेष तौर पर स्त्रियों में बढ़ना।
2. कृषि क्षेत्र में रोजगार 1 : प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ा जो जनसंख्या से कम रहा गैर–कृषि क्षेत्र के रोजगार से बहुत ही कम रहा है, कृषि रोजगार की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई जो कि कृषि क्षेत्र मे खराब प्रदर्शन को दिखलाता है।
3. कृषि क्षेत्र में तकनीकी के समावेश के लिए बहुत थोड़े प्रयास किये गये यहाँ तक कि कृषि के सबसे निचले भाग– संग्रहण, विपणन तथा खुदरा क्षेत्र को निजी के लिए खोज दिया गया है।
4. उदारीकरण की नीतियों ओर रोजगार बढ़ाने के लिए निगम क्षेत्र पर बल दिया गया तथा अतिरिक्त रोजगार का 70: तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होगा, इस क्षेत्र पर अनाश्वयक एवं निराधर विश्वास करना।
5. असंगठित क्षेत्र की इकाइयों का बीमार या कम प्रोन्नत होना। इससे भी रोजगार वृद्धि पर भी मंद प्रभाव पड़ा है।

मूल प्रश्न जिसका उत्तर देना आवश्यक है, यह है: ''विकास का वह विकल्प मॉडल कौन सा है जिसमें देशीय उत्पाद की वृद्धि के साथ रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सकता है?''

विकास के वर्तमान मॉडल की मूल समस्या यह है कि इसमें सकल देशीय उत्पाद को विकास का प्रधान सूचक समझा जाता है। अतः आर्थिक समीक्षा में विकास के प्रमाप के रूप में सकल देशी उत्पाद, प्रतिव्यक्ति सकल देशीय उत्पाद विनियोग और बचत, निर्यात और आयात, थोक कीमत सूचकांक एवं उपभोक्ता कीमत सूचकांक आदि दिए गए हैं परन्तु कहीं भी इनके रोजगार या इनकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन नहीं किए गया है। अन्य शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और रोजगार–वृद्धि को उसकी मॉडल में एक साथ पिरोया नहीं जाता। यह कल्पना की

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

जाती है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार एक आश्रित चर के रूप में विकसित होता है। परन्तु अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि इस बात की समीक्षा की जाए कि सकल घरेलू उत्पाद के भिन्न–भिन्न अंग कौन से हैं और वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इस पहलू की अपेक्षा की जाती रही है। अतः उन मूल्य क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो रोजगार–वृद्धि में योगदान देते हैं और नीतियों का केन्द्र इस क्षेत्रों द्वारा अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर प्राप्त करना होना चाहिए।

सुझाव

उदारीकरण की विफल रणनीति जो श्रमशक्ति के केवल 7: तक ही सीमित है का अनुसरण करना अनुचित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि श्रम शक्ति के 93′ का, जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है, ध्यान दिया जाये।

उदारीकरण को कारण बार–बार श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र की ओर धकेला जा रहा है। इस प्रक्रिया को पलटना होगा ताकि असंगठित क्षेत्र की अधिकाधिक इकाइयाँ उन्नत होकर संगठित क्षेत्र में शामिल हो सकें।

सरकार को सुधारों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए और सुधार प्रक्रिया का इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए ताकि बेराजगारी की परिसमाप्ति और 'काम के अधिकार' को एक बुनियादी हम के तौर पर स्वीकार करने को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए विकास का एक नया मॉडल तैयार करना होगा जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और रोजगार की वृद्धि में समन्वय स्थापित किया जाए।

- लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना इससे रोजगार विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हो सकता है।
- कृषि सकहारी समितियों को खाद्य – विधायन क्रियाओं के लिए मजबूत बनाया जाये ओर इसके विपणन के लिए खादी और ग्राम उद्योग को यह कार्य सौंपा जाये।
- ग्राम आधार संरचना का प्रावधान – रोजगार सृजन का एक और स्रोत बन सकता है।
- गरीबी निवारणी कार्यक्रमों पर भारी व्यव करने की अपेक्षा छोटी–सिंचाई, वाटरशैड विकास पर अधिक साधन किए जाएं जिससे कृषि–उत्पाद उन्न हो तथा रोजगार–विस्तार हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि उद्यमों के विस्तार पर बल देना होगा। इसमें ऐसे उद्योगों को प्रमुखता देनी होगी जो अपना कच्चा माल तथा श्रम बल कृषि क्षेत्र से प्राप्त करें।
- सूचना तकनीकि क्षेत्र को प्रोत्याहित दिया जाना चाहिए ताकि यह ग्रामों एवं दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच सके, परंतु राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना तकनीकि की शिक्षा केवल समृद्ध वर्गों तक ही सीमित न हो जाए बल्कि सहाय्यों एवं विभेदात्मक फीस की प्रणाली द्वारा सूचना तकनीकी की शिक्षा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक पहुँचायी जाये।

निष्कर्ष

इस प्रकार विकास का ऐसा मॉडल ही सकल देशीय उत्पाद में वृद्धि एवं रोजगार–वृद्धि के बीच तालमेल बिठा सकता है ताकि सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रोन्नत हो सके। भारत को पहले 'सभी को रोजगार' उपलब्ध कराना है और संक्रान्ति से गुजर रहे समाज के रूप में इसे अपने अंतिम लक्ष्य 'सभी के लिए अच्छा रोजगार' की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है।

सन्दर्भ –

1. अलघ, वाई0के0 (2005), इण्डियन डेवलपमेंट प्लानिंग एण्ड पॉलिसी, हेलसिंगी इण्ड हेलही, विकास पब्लिकेशन्स।
2. अलघ, वाई0के0 (2010), वर्किंग आउट पावर इकनामिक्स, इण्डियन एक्सप्रेस, 16 जनवरी।
3. वेडे, आर0 (1992), ईस्ट एसियाज इकनामिक सक्सेस, वर्ल्ड पालिटिक्स, टव 44, चच 270.320।
4. डेलांग, जे0बी0 (2001) इण्डिया सिन्स इण्डिपेन्डेन्स–एन एनालिटिक ग्रोथ नरेटिव।
5. पइके, एफ0 (2002), रीजनल डेवलपमेंन्ट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जेनेवा, इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ लेबर इम्पलायमेंट स्टडीज। दिल्ली, 2007, पृ0 308.
6. मिश्र, जे0पी0 भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2007, पृ0 84.